सच्चाई के दम पर
जोश के साथ...

RNI No: UPHIN/2023/86769

www.swarajindianews.com

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

मूल्यः ₹ 02

स्वराज इंडिया

सांध्यकालीन समाचार पत्र

कानपुर, शुक्रवार, 23 मई, 2025
वर्षः 02, अंकः 145, पृष्ठः 8+4

पाकिस्तान के खात्मे का समय आ गया : सीएम योगी

» Pg 12

इनसाइड अमन और अनिरूद्ध की मिलीभगत से संपत्ति विभाग का बंटाधार » Pg03

जल जीवन मिशन में गड़बड़ी पर केंद्र सख्त

100 निरीक्षण टीमें भेजी, टेंडर में गड़बड़ी और खर्च बढ़ने की जांच शुरु

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत चल रही योजनाओं में खर्च और टेंडर की गड़बड़ियों की जांच के लिए 100 निरीक्षण टीमों को 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 135 जिलों में भेजा है। यह कदम तब उठाया गया जब योजना में भारी लागत बढ़ने और टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी की रिपोर्टें सामने आईं। जल जीवन मिशन के तहत काम में गड़बड़ियों और बढ़ते खर्च की जांच के लिए केंद्र सरकार ने 19 मई को 100 निरीक्षण टीमों को 135 जिलों में भेजा है। यह कदम उन चिंताओं के बीच उठाया गया है, जिनमें कहा गया है कि कई योजनाओं में टेंडर नियमों में बदलाव के बाद खर्च जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है।

जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा डाले गए आंकड़ों की जांच में सामने आया है कि 2022 में टेंडर से जुड़े नियम बदले गए, जिससे राज्य अब पहले से तय लागत से ज्यादा रेट पर टेंडर दे सकते हैं जिससे 14,586 योजनाओं की लागत में कुल 16,839 करोड़ रुपये (लगभग 14.58 प्रतिशत) की बढ़ोतरी हुई है। पहले के नियमों के अनुसार, अगर किसी योजना की लागत बढ़ती थी, तो उसका बोझ राज्य सरकार को उठाना होता था और केंद्र की तरफ से कोई अतिरिक्त पैसा नहीं मिलता था लेकिन 2022 में नियम बदलकर 'टेंडर प्रीमियम' को मान्य कर दिया गया जिससे अब राज्य सरकारें ज्यादा बोली लगाने वालों को भी टेंडर दे सकती हैं। इस बदलाव के बाद, कई योजनाओं की लागत अनुमान से बहुत ज्यादा हो गई। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लागत बढ़ी, जहां केवल 4 प्रतिशत योजनाएं थीं लेकिन उन्होंने 64 प्रतिशत अतिरिक्त खर्च

सामने आई मुख्य बातें

कई योजनाओं में टेंडर के बाद जो खर्च हुआ, वह राज्य सरकारों द्वारा पहले जो अनुमान लगाया गया था, उससे काफी ज्यादा था। लगभग आधे से ज्यादा मामलों में, खर्च अनुमानित लागत से कम से कम दस प्रतिशत ज्यादा था। कुछ बड़ी योजनाओं में तो यह बढ़ोतरी करोड़ों रुपये की थी।मध्य प्रदेश में कुल योजनाओं की संख्या कम थी, लेकिन वहां हुई लागत वृद्धि पूरे देश में हुई कुल बढ़ोतरी का लगभग 64 प्रतिशत हिस्सा थी। कुछ राज्यों में यह बढ़ोतरी ज्यादा नजर आई, जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु में।

क्या असर हो सकता है?

जल जीवन मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है हर ग्रामीण घर तक नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना। ऐसी फाइंडिंग्स के सामने आने से स्थानीय स्तर पर कई तरह के बुरा असर पड़ सकते हैं। यदि केंद्र सरकार फंड में कटौती करती है या राज्य सरकारें जांच और प्रक्रियाओं में उलझ जाती हैं, तो उन गांवों में जहां अब तक पाइपलाइन नहीं बिछाई गई है, वहां का काम रुक सकता है या उसकी रफ्तार धीमी हो सकती है।

में योगदान दिया। इस मुद्दे को देखते हुए, सरकार अब पूरे देश में योजनाओं की स्थिति की जांच कर रही है।

2022 में नियमों में हुआ बदलाव? : 21 जून 2022 को जल शक्ति मंत्रालय ने इन नियमों में बदलाव किया। नए नियमों में कहा गया कि किसी योजना की 'मंजूर लागत' वही मानी जाएगी जो एक खुली, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी टेंडर प्रक्रिया के जरिए तय की गई हो। इन तीन सालों में कुल 1,03,093 योजनाएं 600 जिलों में मंजूर की गईं, जो 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में फैली थीं। इन योजनाओं की लागत 3,90,732 करोड़ रुपये थी, जो जल जीवन मिशन की शुरुआत से अब तक मंजूर की गई सभी योजनाओं की कुल राशि का 47 प्रतिशत हिस्सा है।

जल जीवन मिशन को लेकर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने दी चेतावनी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जल जीवन मिशन परियोजना में लापरवाही बरतने वाली एजेंसियों को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि गड़बड़ी पाए जाने पर दोषियों को जेल भेजा जाएगा।

उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जल जीवन मिशन की प्रगति का जायजा लेने और गर्मी के महीनों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे। पहले चरण में वे बुंदेलखंड और विंध्य के नौ जिलों में औचक निरीक्षण करेंगे। मंगलवार को लखनऊ में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को हर जिले में घोषित हर घर जल गांव योजना की सूची तैयार करने और परियोजनाओं का खाका तैयार करने के निर्देश दिए।

बैठक में जल शक्ति मंत्री ने परियोजनाओं में लापरवाही बरतने वाली एजेंसियों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर दोषियों को जेल भेजा जाएगा। इसके साथ ही, थर्ड पार्टी एजेंसियों को नियमित निरीक्षण और दैनिक रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए। नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने मिर्जापुर में जल जीवन मिशन की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई और कार्यदायी संस्था रामकी बाबा और मेघा के कार्यों की जांच के आदेश दिए। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के एक्शन से अधिकारियों ने भी निगरानी बढ़ा दी है।

ब्लॉक स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश

प्रमुख सचिव ने सभी एडीएम और अधिशासी अभियंताओं को ब्लॉक स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद और अन्य विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे। स्वतंत्र देव सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बुंदेलखंड क्षेत्र में जल जीवन मिशन की परियोजनाओं की समीक्षा के लिए विभागीय अधिकारियों संग बैठक की। जल जीवन मिशन का लक्ष्य हर ग्रामीण परिवार को किफायती शुल्क पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। यूपी में इस योजना से लाखों को लाभ मिल रहा है। सरकार का प्रयास ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ जल की उपलब्धता बढ़ाने और जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

बांग्लादेश की सेना नाराज

मो. यूनुस जल्द दे सकते हैं इस्तीफा!

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। : बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं। कहीं बांग्लादेश की सेना की नाराजगी तो इसकी वजह नहीं है! बीबीसी की बांग्ला सेवा ने गुरुवार आधी रात को छात्रों के नेतृत्व वाली नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख एनहिद इस्लाम के हवाले से यह खबर दी। इसमें कहा गया कि यूनुस को लगता है कि राजनीतिक दलों के बीच सहमति नहीं बन पाने के कारण काम करना मुश्किल हो रहा है।

नाहिद इस्लाम ने मीडिया समूह से कहा, 'हम आज सुबह से सर (यूनुस) के इस्तीफे की खबर सुन रहे हैं। इसलिए मैं उस मुद्दे पर

चर्चा करने के लिए सर से मिलने गया था। सर ने भी यही कहा कि वे इस बारे में सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि स्थिति ऐसी है कि वे काम नहीं कर सकते।' गौरतलब है कि नाहिद इस्लाम अंतरिम सरकार में शुरुआत में खुद यूनुस के सलाहकार के तौर पर काम कर चुके हैं। हालांकि, इसी साल उन्होंने यूनुस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने का एलान कर दिया था।

महिला का मातृत्व अवकाश उसका अधिकार

शुक्रवार को मातृत्व अवकाश से जुड़ा एक अहम फैसला सुनाया

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मातृत्व अवकाश से जुड़ा एक अहम फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि अनुसार मातृत्व अवकाश मातृत्व लाभ का एक अभिन्न अंग है और महिलाओं के प्रजनन अधिकारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मातृत्व अवकाश से जुड़ा एक अहम फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि कोई भी संस्था किसी महिला को मातृत्व अवकाश के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती।

यह ऐतिहासिक आदेश तमिलनाडु की एक

महिला सरकारी शिक्षिका की आरे से दायर याचिका पर आया। महिला को दूसरी शादी से हुए बच्चे के जन्म के बाद मातृत्व अवकाश देने से मना कर दिया गया था।

अपनी याचिका में महिला ने कहा कि उसे मातृत्व अवकाश देने से इस आधार पर मना कर दिया गया कि उसकी पहली शादी से दो बच्चे हैं। तमिलनाडु में नियम है कि मातृत्व लाभ केवल पहले दो बच्चों को ही मिलेगा।

याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने अपनी पहली शादी से हुए दो बच्चों के लिए कोई मातृत्व अवकाश या लाभ नहीं लिया है। महिला ने यह भी दावा किया कि वह अपनी दूसरी शादी के बाद ही सरकारी सेवा में आई है।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता के.वी. मुथुकुमार ने कहा कि राज्य के निर्णय से उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि उसने पहले तमिलनाडु के मातृत्व लाभ प्रावधानों का लाभ नहीं उठाया था।

काशीराम हॉस्पिटल में डीएम का छापा, 64 गैरहाजिर मिले

अनुपस्थित कर्मचारियों एवं डाक्टरों का एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश हुए

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा शुक्रवार को काशीराम हॉस्पिटल का किया औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 64 कर्मचारी एवं डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए अनुपस्थित कर्मचारियों एवं डाक्टरों का आज का वेतन रोकने के निर्देश दिए।

शासन की प्राथमिकता के अनुरूप आम जनमानस को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह ने आज सुबह 8:35 बजे काशीराम हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुल 64 डॉक्टर कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए।

इस पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी अनुपस्थित डॉक्टरों का एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए।

साथ ही उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी डॉक्टर शासन के दिशा-निर्देशों का समय से अनुपालन सुनिश्चित करें और नियमित रूप से ओपीडी में उपस्थित रहकर नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएं, ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

जेके कैंसर: स्थापना के 62 साल बाद बनेंगे तीन नए विभाग

शासन की मिली मंजूरी रोगियों को मिलेंगी खास सुविधाए

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। इंस्टीट्यूट के निदेशक एवं प्रोफेसर डॉ. एसएन प्रसाद ने बताया कि कैंसर रोगियों के ऑपरेशन संस्थान में होने लगेंगे। अभी दो एनीस्थेटिस्ट हैं, लेकिन पूरा विभाग खुल जाने से यहां और भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगीं। जटिल से जटिल सर्जरी में आसानी होगी। कानपुर में जेके कैंसर इंस्टीट्यूट में स्थापना के 62 साल बाद तीन नए विभाग बनेंगे। शासन ने सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, एनेस्थीसिया और पैथोलॉजी विभाग के लिए पद सृजित कर दिए हैं। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग को भी अपडेट किया जाएगा। इससे कैंसर रोगियों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें जांच, ऑपरेशन और इंटेंसिव केयर की सुविधा मिल सकेगी। यह विभाग इसी वर्ष चालू हो जाएंगे।

जेके कैंसर इंस्टीट्यूट अब तक रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग के सहारे चल रहा है। कैंसर की जांच के लिए पिछले कई वर्षों से बायोप्सी की भी सुविधा नहीं है।

रोगियों को बायोप्सी जांच के लिए जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी विभाग जाना पड़ता रहा है। नए विभाग खुलने से रोगियों को सभी सुविधाएं इंस्टीट्यूट में मिलने लगेंगी। विभाग खुलने से कैंसर के इलाज के विशेषज्ञों की संख्या बढ़ेगी। प्रशिक्षित पैरा मेडिकल स्टाफ भी रहेगा।

1963 के बाद पहली बार खुलेंगे विभाग

इंस्टीट्यूट के निदेशक एवं प्रोफेसर डॉ. एसएन प्रसाद ने बताया कि कैंसर रोगियों के ऑपरेशन संस्थान में होने लगेंगे।

अभी दो एनीस्थेटिस्ट हैं, लेकिन पूरा विभाग खुल जाने से यहां और भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगीं। जटिल से जटिल सर्जरी में आसानी होगी।

नवीनतम तकनीक से पैथोलॉजिकल जांचें की जा सकेंगी। सभी विभाग छह महीने से लेकर साल भर के अंदर काम करना शुरू कर देंगे। यह विभाग वर्ष 1963 में संस्थान की स्थापना के बाद पहली बार खुलेंगे।

विभागों की स्थिति

सर्जिकल ऑन्कोलॉजी–एक प्रोफेसर, एक एसोसिएट प्रोफेसर, एक असिस्टेंट प्रोफेसर, छह रेजीडेंट, एक सिस्टर, 21 स्टाफ नर्स समेत कुल 36 लोगों का स्टाफ रहेगा। आउटसोर्सिंग में मेडिकल सोशल वर्कर, ओटी टेक्नीशियन समेत 28 लोगों का स्टाफ होगा।

रोगियों को मिलेंगी ये सुविधाएं

कैंसर रोगियों की अत्याधुनिक पैथोलॉजिकल जांचें होंगी।
मार्कर जांचें होने से रोगियों के मर्ज का पहले पता लग जाएगा।
विभिन्न प्रकार के कैंसर रोगियों को विशेषज्ञ इलाज मिलेगा।
स्पेशलिस्ट सर्जन रोगियों का आपरेशन करेंगे।
आईसीयू की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
कैंसर रोगियों के पेन मैनेजमेंट की व्यवस्था रहेगी।
अत्याधुनिक तकनीक से रेडियोथैरेपी की व्यवस्था रहेगी।
विभागों बनने से विभिन्न संसाधनों का लाभ मिलेगा।

एनेस्थीसिया– एक प्रोफेसर, एक एसोसिएट प्रोफेसर, एक असिस्टेंट प्रोफेसर, तीन सीनियर और तीन जूनियर रेजीडेंट, एक सिस्टर, 21 स्टाफ नर्स समेत कुल 36 लोगों का स्टाफ रहेगा। आउटसोर्सिंग में मेडिकल सोशल वर्कर, आईसीयू टेक्नीशियन समेत 28 लोगों का स्टाफ होगा।

पैथोलॉजी विभाग– एक प्रोफेसर, एक एसोसिएट प्रोफेसर, एक असिस्टेंट प्रोफेसर, तीन सीनियर और तीन जूनियर रेजीडेंट, एक सिस्टर, 21 स्टाफ नर्स समेत कुल 36 लोगों का स्टाफ होगा। आउटसोर्सिंग में मेडिकल सोशल वर्कर, लैब टेक्नीशियन, सेनीटरी वर्कर समेत 28 लोगों का स्टाफ रहेगा।

रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग– दो प्रोफेसर, दो एडीशनल प्रोफेसर, दो एसोसिएट प्रोफेसर, दो असिस्टेंट प्रोफेसर, छह सीनियर और छह जूनियर रेजीडेंट, दो सिस्टर, 42 स्टाफ नर्स समेत कुल 72 लोगों का स्टाफ रहेगा। आउटसोर्सिंग में मेडिकल सोशल वर्कर, रेडियोथैरेपी टेक्नीशियन समेत 56 लोगों का स्टाफ होगा।

(नगर निगम कानपुर के कई अनुभागों में चरम पर धांधली)

लिपिक अमन और प्रभारी अनिरूद्ध सिंह की मिलीभगत से संपत्ति विभाग का बंटाधार

सुधीर कुमार (नगर आयुक्त कानपुर)

किसी प्रकार की हेराफेरी और मनमानी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सपंत्ति विभाग में चल रहे खेल की जानकारियां मिली हैं, रिपोर्ट तलब कर कार्रवाई की जाएगी।
सुधीर कुमार
नगर आयुक्त कानपुर

» जोनल अधिकारी अनिरूद्ध सिंह की अनदेखी के चलते नगर निगम की कई संपत्तियों पर हो गए कब्जे

» निगम की कई संपत्तियों से बिचैलिए कमा रहे लाखों लेकिन नगर निगम के खजाना को नहीं मिलता धेला !

प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। नगर निगम कानपुर लगातार अपनी आय बढाने के लिए नए नए स्त्रोत बढा रहा है। मेयर प्रमिला पांडेय और नगर आयुक्त सुधीर कुमार राजस्व बढाने के लिए समीक्षा बैठकें करते हैं लेकिन उनके कुछ मातहत एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। उनके लिए किसी अफसर और नेता का कोई निर्देश मायने नहीं रखता है। मामला नगर निगम की संपत्ति विभाग का है। यहां पर जब से जोनल अधिकारी-2 अनिरूद्ध सिंह को जब से सपंत्ति अनुभाग का चार्ज मिला है तब से यह अनुभाग रसातल में जा रहा है। अफसरों एवं बाबुओं और बिचैलियों की आय तो बढ रही है लेकिन नगर निगम खजाने में उंट के मुंह में जीरा की तरह राजस्व जा रहा है। अनिरूद्ध सिंह की अनदेखी के चलते लिपिक अमन निगम दलालों से मिलकर संपत्ति विभाग की कई संपत्तियों का बंटाधार करने में जुटा है। हालांकि, कई प्रकरण नगर आयुक्त के संज्ञान में पहुंचे हैं।

उप्र के औद्योगिक महानगरों में शामिल कानपुर नगर निगम की कई वेशकीमती जमीनें, पार्क, बारातशालाएं, धर्मशालाएं और अन्य इमारतें शहर में गुमनाम होती जा रही हैं। इन संपत्तियों के रखरखाव का जिम्मा संपत्ति विभाग देखता है लेकिन संपत्ति प्रभारी की मिलीभगत से संपत्तियों में कब्जे हो रहे हैं। जिस जोन 2 के अनिरूद्ध सिंह प्रभारी हैं

उसी जोन के कई बारातशालाओं में स्थानीय स्तर पर कब्जा है। इसके पूरे शहर में बारातशालाएं किस हालात में हैं कुछ नहीं पता है।

बीते दिनों से मोतीझील के लॉन आवंटन का प्रकरण नगर निगम में चर्चा का विषय बना हुआ है। तत्कालीन नगर आयुक्त शिवशरणप्पा जीएन के कार्यकाल में टेंडर के माध्यम से मोतीझील के लॉन नंबर 1 और 2 तीन करोड रूपए से टेंडर करके 90 दिन के लिए मेला संस्था को दिए गए थे। इस बार तीन बार टेंडर जारी हो चुके हैं लेकिन कोई बोलीदाता नहीं आ रहा है। जब कि इस बार रेट कम कर दिए गए हैं।

पहली बार टेंडर में 2.50 करोड, दूसरी बार 2 करोड रूपए और तीसरी बार 1 करोड रूपए कर दिए गए हैं।

इसके बाद भी टेंडर लेने कोई नहीं आया। अब हालांकि मात्र 40 दिन का समय बचा है, ऐसे में अब मेला के लिए लॉन की बुकिंग होना नहीं दिख रहा है। विभागीय सूत्रों का दावा है कि संपत्ति प्रभारी अनिरूद्ध सिंह की अनदेखी और लिपिक अमन निगम की मनमानी के चलते बोलीदाता नहीं आ रहे हैं। इसका खामियाजा नगर निगम के खजाने को लग रहा है।

बिना अनुमति अगले साल की कर ली बुकिंग

संपत्ति प्रभारी और लिपिक अमन निगम की मिलीभगत से अलगे वित्तीय वर्ष के लिए लॉन नंबर 2 मात्र 26 लाख रूपए में 40 दिन के लिए बुक कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि बिना टेंडर बुकिंग के लिए न तो मेयर, न ही नगर आयुक्त से सहमति ली गई सिर्फ कुछ पैसों के लालच में खेल कर दिया गया। जब कि लॉन नंबर 2 एडवांस बुक करने से अब कोई भी मेला संस्था ग्राउंड नहीं बुक कर पाएगी क्यों कि लॉन 2 बीच में है। ऐसे में पहले से बुक वाली संस्था की मनमानी चलेगी। इसका सीधा सीधा नुकसान नगर निगम को झेलना पडेगा। इस संबंध में संपत्ति प्रभारी से बात करने का प्रयास किया गया लेकिन वह स्वराज इंडिया की खबरों से इतने तिलमिलाए नजर आए कि कोई जवाब देने की बजाय अनर्गल टिप्पणी करते हुए भागते हुए निकल गए।

रोहिंग्या के पकड़े जाने से सक्रिय हुईं सुरक्षा एजेंसिया

मो.साहिल और परिजनों से पूछताछ

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। म्यांमार से आकर शुक्लागंज में बीते आठ साल से रह रहे रोहिंग्या के परिवार वालों का कहना है कि वह लोग पूरे परिवार के साथ बांग्लादेश चले जाएंगे। वहां पर उन लोगों के कई रिश्तेदार हैं, लेकिन म्यांमार नहीं जाएंगे।कानपुर में रोहिंग्या मो. साहिल के पकड़े जाने के बाद पुलिस, आईबी, इंटेलीजेंस, मिलिट्री इंटेलीजेंस, एसटीएफ और एटीएस सक्रिय हो गई हैं। शहर में 16 संदिग्ध स्थानों पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों का सत्यापन शुरू किया जा रहा है। पुलिस ने मो. साहिल और उसके भाईयों की कॉल डिटेल निकलवाई।

आधार कार्ड कैसे बना, जांच के बाद होगी कार्रवाई

इसमें उनकी सबसे ज्यादा शुक्लागंज और उन्नाव के लोगों से बातचीत होने की जानकारी मिली। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी सामने आए हैं। एसपी उन्नाव और सुरक्षा एजेंसियों से इसको साझा किया गया। डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि आईबी और लोकल इंटेलीजेंस से जानकारी मिली है। कानपुर कमिश्नरेट के 16 क्षेत्रों में संदिग्ध लोग रह रहे हैं। यह बांग्लादेशी या रोहिंग्या हो सकते हैं।

म्यांमार नहीं जाएंगे, वहां मार डाले जाएंगे

म्यांमार से आकर शुक्लागंज में बीते आठ साल से रह रहे रोहिंग्या के परिवार वालों का कहना है कि वह लोग पूरे परिवार के साथ बांग्लादेश चले जाएंगे। वहां पर उन लोगों के कई रिश्तेदार हैं, लेकिन म्यांमार नहीं जाएंगे। यह कहना मो. साहिल की पत्नी अजीदा, उसकी मां रोहिमा, बहन सहनवारा और देवरानी नूरखाइदा का है। उन्होंने कहा कि म्यांमार में मुसलमान नहीं रहते वहां उनकी जान को खतरा है। वहां वाले उनको मार डाला जाएगा।

डीसीपी पूर्वी के मुताबिक मो. साहिल ने बताया कि सभासद के सत्यापन के बाद उसका आधार कार्ड बना था। पुलिस ने जब सभासद से इस संबंध में पूछताछ की तो उसने किसी प्रकार का प्रमाणपत्र देने से इन्कार कर दिया। जिसके बाद विवेचक ने आधार कार्ड बनाने वाली एजेंसी से जानकारी मांगी है कि आधार बनाने के लिए जिस कागज का इस्तेमाल किया गया वह किसके द्वारा प्रमाणित किया गया था। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

भाई के साथ शहर आया, शादी कर बसाया घर

मो. साहिल ने पूछताछ में बताया कि वह पिता मो. याहिया, मां रोहिमा बेगम व भाई अनवर, हबीउल्लाह और असमत के साथ शहर आया था। यहां उसने अजीदा बेगम से निकाह किया था। तीन वर्ष की बेटी हबीबा है। वहीं भाई अनवर ने नूर कैदा से शादी की। वह वर्तमान में गर्भवती है। वर्ष 2021-22 में उसकी बड़ी बहन शेनुआरा बेगम भी पति जुनैद व दो बच्चों के साथ शुक्लागंज आ गई। एक बेटा शुक्लागंज में पैदा हुआ, जबकि छह माह पहले छोटी बहन ताहिरा बेगम पति व बच्चों के साथ वापस बांग्लादेश चली गई।आधार कार्ड के साथ कौन कौन से दस्तावेज लगाए गए हैं। इसका पूरा रिकार्ड और डाटा लखनऊ और बंगलूरू में रखा जाता है। कमिश्नरेट पुलिस के मुताबिक लखनऊ सेंटर को पत्र भेज दिया गया है। अगर सभासद ने उसे सत्यापन पत्र दिया होगा तो वो भी आधार कार्ड के साथ लगा होगा। डीसीपी पूर्वी ने बताया कि दस्तावेज सही पाए गए तो मदद करने वाले को भी केस में शामिल किया जाएगा।

असम में भी आधार कार्ड बनाने का हुआ था प्रयास

कोतवाली इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद पांडेय के मुताबिक आरोपी जब बांग्लादेश से भारत घुसे थे तो उसके साथ मौजूद एजेंट ने बरपेटा असोम में भी आधार कार्ड बनवाने का प्रयास किया था, लेकिन किसी कारण से वहां पर आधार बन नहीं सका। फिर शुक्लागंज में आधार कार्ड को बनवाया।

बहन के पास मिले वैध कागजात

मो. साहिल की बहन ताहिरा बेगम पति अमीन के साथ वैध कागजात के साथ भारत में रह रही है। उसके पास से विदेशी पंजीकरण का फार्म सी मिला है। यह 2027 तक वैध है। उसके घर में दो और लोग थे। कार्रवाई के बाद से दोनों गायब है।

सम्पादकीय

किशोरों के भटकाव की गंभीर चुनौती

कैथल जनपद के गांव धनौरी में दो किशोरों की निर्मम हत्या की हृदयविदारक घटना उद्वेलित करने वाली है। चौदह-पंद्रह साल के दो किशोरों की गला रेतकर हत्या कर देना और वह भी उनके हमउम्र साथियों द्वारा, हर संवेदनशील इंसान को हिला देने वाली घटना है। जाहिर है दसवीं-ग्यारहवीं के छात्रों की क्रूर हत्या हमारे समाज में बढ़ती आक्रामकता और संवेदनहीनता को भी दर्शाती है। बताते हैं हत्या में शामिल युवक गांव के ही थे और कुछ दिन पहले किशोरों को धमकाने उनके घर आए थे। इस बाबत प्रकाशित खबरों के अनुसार मारे गए किशोरों पर हत्या आरोपियों ने आरोप लगाया था कि वे उनकी बहनों से छेड़खानी करते थे। निश्चय ही ऐसे छेड़खानी के कथित आरोप को नैतिक दृष्टि से अनुचित ही कहा जाएगा, लेकिन उसका बदला हत्या कदापि नहीं हो सकती। यह हृदयविदारक है कि एक मृतक किशोर अरमान पांच बहनों का अकेला भाई था। घटना से उपजी त्रासदी से अरमान के परिवार पर हुए वज्रपात को सहज महसूस किया जा सकता है।

उनके लिये जीवनभर न भुलाया जा सकने वाला दुख पैदा हुआ है। बहरहाल, किसी परिवार की उम्मीदों का यूं कत्ल होना मर्मांतक ही है। लेकिन सवाल ये है कि चौदह-पंद्रह साल के किशोरों पर यूं किन्हीं लड़कियों को छेड़ने के आरोप क्यों लग रहे हैं? पढ़ने-लिखने की उम्र में ये सोच कहां से आ रही है? क्यों हमारी परिवार संस्था बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं दे पा रही है ताकि वे किसी की बेटी व बहन को यूं परेशान न करें? उन्हें क्यों लगता है कि किसी लड़की को छेड़ा जाना चाहिए? क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था में नैतिक शिक्षा का वह पक्ष तिरोहित हो चला है, जो उन्हें ऐसा करने से रोकता है? क्या शिक्षक छात्रों को सदाचारी व नैतिक मूल्यों का जीवन जीने की प्रेरणा देने में विफल हो रहे हैं? हत्या की घटना हत्यारों की मानसिकता पर भी सवाल उठाती है कि उन्होंने क्यों सोच लिया कि छेड़खानी का बदला क्रूर ढंग से गला काटना हो सकता है?दरअसल, दशकों तक बॉलीवुड की हिंदी फिल्मों ने समाज में जिस अपसंस्कृति का प्रसार किया, आज हमारा समाज उसकी त्रासदी झेल रहा है। आम तौर पर फिल्मों में हीरो हिरोइन से छेड़खानी करता और उसे परेशान करता नजर आता था। बाद में फिल्म की पटकथा में नायिका उसी हीरो के आगे समर्पण करती नजर आती थी। फिर फिल्म की पटकथा इस छेड़खानी को प्रेम कथा और विवाह में तब्दील कर देती है। कालांतर समाज के किशोरवय और युवाओं में यह संदेश गया कि निजी जीवन में यही छेड़खानी उनकी प्रेम कहानी में तब्दील हो सकती है। फिर बची-खुची कसर हमारे टीवी धारावाहिकों की संवेदनहीन व क्रूर-कथाओं ने पूरी कर दी। बॉक्स आफिस की सफलता और टीआरपी के खेल ने मनोरंजक कार्यक्रमों में ऐसी नकारात्मकता भर दी कि समाज में इसे न्यू नॉर्मल मानने की सोच पैदा हुई। कहीं न कहीं पारिवारिक संस्था व शिक्षा व्यवस्था इस सोच को खारिज करने में चूकी है। इंटरनेट के विस्तार और सोशल मीडिया के प्रसार से स्वच्छंद यौन व्यवहार का ऐसा अराजक रूप सामने आया कि जिसने किशोरों व युवकों को पथभ्रष्ट करना शुरू कर दिया। आज संकट ये है कि हर किशोर के हाथ में आया मोबाइल उसे समय से पहले वयस्क बना रहा है। जिस पर न परिवार का नियंत्रण है और न ही शिक्षकों का। कोरोना संकट के दौरान ऑनलाइन कक्षाओं की अपरिहार्यता ने विद्यार्थियों को मोबाइल उपयोग की स्वच्छंदा दी। आज उन्हें प्रभावित करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व एप पश्चिमी अपसंस्कृति से संचालित हैं।

परमाणु बम का हौवा बरकरार रहने की आशंका

मनोज जोशी

हाल ही में भारत-पाकिस्तान टकराव के दौरान उभरे हालात के मद्देनजर भारतीय उपमहाद्वीप में परमाणु युद्ध के खतरे को हलके में लेना दुस्साहस ही कहा जाएगा। पाकिस्तान की परमाणु धमकी जगजाहिर है। वहीं भारत का नया दावा भी अहम है कि वह परमाणु ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेगा। दरअसल, बड़ा खतरा पूर्ण युद्ध का है। शेक्सपियर के मशहूर नाटक मैकबेथ के चरित्र बैंको के भूत की तरह, परमाणु हथियारों का साया हाल के दशकों में भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्षों पर रह-रहकर मंडराता रहा है। नकारने के बावजूद, ऑपरेशन सिंदूर पर भी यह मंडराता रहा।

पिछले इतिहास को देखने पर, वास्तविक परमाणु युद्ध का जोखिम हालांकि बहुत कम, लगभग नगण्य लगता रहा है। लेकिन जिस प्रकार की घटनाएं सामने आई हैं, कई राहें दिखाई देनी लगी हैं,जो भयावह अंजाम की ओर ले जा सकती हैं। इन संभावनाओं की गंभीरता ने ही अमेरिका को इस युद्ध से दूरी बनाए रखने के अपने पहले रुख को तजकर, त्वरित सक्रिय कूटनीतिक प्रयास करने और दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम करवाने में मदद करने को सक्रिय किया। भारत का कहना है कि यह युद्ध विराम द्विपक्षीय रहा, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि यह 'अंकल सैम' (ट्रंप) की मध्यस्थता से बना है, जो अब हमें इसके बारे में बार-बार याद दिलाते नहीं थक रहे।

बीती 12 मई को कतर की अपनी यात्रा की पूर्व संध्या पर व्हाइट हाउस में बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा : 'मेरे प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण और तत्काल युद्धविराम करवाने में मदद की, मुझे लगता है यह स्थायी होगा, इस तरह बड़ी संख्या में परमाणु हथियारों से लैस इन दो मुल्कों के बीच खतरनाक संघर्ष समाप्त हो गया'। इससे एक दिन पहले, उन्होंने 'मौजूदा आक्रामकता' को खत्म करने के लिए भारतीय और पाकिस्तानी नेतृत्व की प्रशंसा की थी और कहा कि 'लाखों भले और निर्दोष लोग अन्यथा मारे जाते'।टकराव बनने से पहले ही, पाकिस्तान ने परमाणु धुड़की देनी शुरू कर दी थी। भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बाद, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया कि पानी को रोकने या मोड़ने के किसी भी प्रयास को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा और इसका जवाब राष्ट्रीय शक्ति और उपलब्ध तमाम संसाधन का उपयोग करके दिया जाएगा'। यहां पर 'तमाम संसाधन' का अभिप्राय स्पष्ट रूप से परमाणु हथियार

था। फिर, जैसे-जैसे संकट बढ़ता गया, पाकिस्तान और ज्यादा परमाणु धुड़कियां देने लगा। बता दें कि 10 मई को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रीय कमान प्राधिकरण की बैठक बुलाई, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के अलावा परमाणु हथियारों से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने वाली शीर्ष संस्था है। बाद में पाकिस्तान आसानी से इससे मुकर गया। परमाणु हथियारों से संबंधित घटनाक्रमों को लेकर बहुत सी भ्रामक सूचनाएं फैलीं। ऐसी ही एक खबर में बताया गया कि किराना हिल्स पर भारतीय हमले के तुरंत बाद, जहां कथित तौर पर कुछ पाकिस्तानी परमाणु हथियार रखे हुए हैं, एक बीचक्राफ्ट सुपर किंग एयर 350 विमान सरगोधा में उतरा है - जो कथित तौर पर अमेरिकी ऊर्जा विभाग का है। और इसकी उपस्थिति का परमाणु एंगल से कुछ लेना-देना नहीं था।भारत ने इस बात से इनकार किया कि उसने सरगोधा के नज़दीक मुशाफ एयरबेस से लगभग 15 किमी. दूर स्थित किराना हिल्स पर कोई हमला किया है। लेकिन हां, किराना हिल्स के मुहाने पर स्थित दो सैन्य ठिकानों पर भारतीय हमले के सबूत अवश्य हैं। यहां स्पष्ट करना होगा कि रावलपिंडी के पास नूर खान वायुसेना अड्डा, कराची के पास मलीर और किराना हिल्स पर भारतीय हमलों का मकसद कुछ ऐसा ही संदेश देना था। क्योंकि इन जगहों पर या इनके आसपास ही कहीं पाकिस्तान के परमाणु हथियार रखे होने के कयास हैं।यह 12 मई को और भी स्पष्ट हो गया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि 'भारत परमाणु ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेगा और परमाणु ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक हमला करेगा'।यह एक नया सैद्धांतिक रुख है, क्योंकि पिछले 40 वर्षों में भारत ने सीमा पार से चलाए जा रहे आतंकवाद का सामना किया है, यह परमाणु कारक ही था जिसने भारत के हाथ बांध रखे थे।

फिर देश की जीवन रेखा बन जाएगा जल संचयन

वर्षा जल संरक्षण अभियान

दीपक कुमार शर्मा

वर्षा जल संचयन एक पारंपरिक लेकिन अत्यंत प्रभावी तकनीक है, जो वर्षा के जल को इकट्ठा कर विभिन्न उपयोगों हेतु संग्रहीत करती है। भारत में बढ़ते जल संकट और शहरीकरण के चलते इसकी महत्ता और आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। यह एक पर्यावरण-संवेदनशील, कम लागत और टिकाऊ समाधान प्रदान करता है। भारत में वर्षा जल संचयन बाजार का मूल्य वर्ष 2024 में लगभग 263 मिलियन अमेरिकी डॉलर आंका गया था। इसके 2030 तक 378 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। वर्षा जल संचयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वर्षा के जल को इकट्ठा करके, संगृहीत कर विभिन्न उपयोगों हेतु प्रयोग किया जाता है। जिससे यह जल व्यर्थ बहने के बजाय एक उपयोगी संसाधन बन जाता है।

एक टिकाऊ तकनीक छतों, ज़मीन की सतहों अथवा अन्य संग्रहण क्षेत्रों से वर्षा जल को पाइपों या नालियों के माध्यम से टंकियों, हौदों अथवा जलाशयों में पहुंचाकर संचयित करती है। यह एक प्राचीन परंपरा है, जिसे आज जल संकट और पर्यावरणीय चुनौतियों को देखते हुए पुनः अपनाया जा रहा है।संगृहीत वर्षा जल का उपयोग सिंचाई, घरेलू जरूरतों, औद्योगिक प्रक्रियाओं और भूजल पुनर्भरण के लिए किया जा सकता है। यह न केवल नगरपालिका जल आपूर्ति पर निर्भरता को घटाता है, बल्कि मिट्टी के कटाव को रोकने और शहरी बाढ़ को कम करने में भी सहायक होता है। इसके अतिरिक्त, यह आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है और अनिश्चित वर्षा वाले क्षेत्रों में एक स्थायी जल स्रोत उपलब्ध कराता है।

यह पर्यावरण-मित्र विधि विशेष रूप

से शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में अत्यंत लाभदायक है, जहां जल संसाधनों की भारी कमी है। यह एक कम लागत और सरल पद्धति है, जिसे व्यक्तिगत आवासों से लेकर सामुदायिक परियोजनाओं तक विभिन्न स्तरों पर अपनाया जा सकता है। यदि इसे शहरी और ग्रामीण योजना में समाहित किया जाए तो जल संकट का समाधान संभव है और टिकाऊ जल प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकता है।केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जल प्रबंधन को लेकर सख्त नीतियां लागू की गई हैं। जैसे कि 'अमृत मिशन' में वर्षा जल संचयन को शहरी जल संकट के समाधान का अभिन्न अंग बनाया गया है। तमिलनाडु जैसे राज्यों ने सभी भवनों में वर्षा जल संचयन को अनिवार्य कर दिया है, जो अब देश के अन्य हिस्सों में भी लागू किया जा रहा है। तमिलनाडु ने यह पहल 2001 में शुरू की गई थी। इसके अलावा, स्थानीय निकाय करों में छूट और वित्तीय सहायता भी प्रदान करते हैं जिससे इन प्रणालियों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलता है। 2023 में केंद्रीय भूजल बोर्ड के अध्ययन के अनुसार, तमिलनाडु में निगरानी किए गए 72 फीसदी कुओं में भूजल स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जैसे अनियमित वर्षा और सूखे की घटनाओं ने वर्षा जल संचयन की आवश्यकता को बढ़ा दिया है। गैर-सरकारी संगठनों, स्कूलों और मीडिया द्वारा चलाए जा रही जागरूकता अभियानों ने लोगों को इस दिशा में प्रेरित किया है।भारत का शहरीकरण तीव्र गति से हो रहा है—2021 में लगभग 500 मिलियन की शहरी आबादी 2031 तक 600 मिलियन तक पहुंचने की संभावना है। शहरी क्षेत्र जहां कंक्रीट का वर्चस्व होता है, वहां वर्षा जल का प्राकृतिक भूजल पुनर्भरण बहुत कम हो पाता है। ऐसी स्थिति में वर्षा जल संचयन एक अनिवार्य आवश्यकता बन गया है।

दरअसल, इस अभियान की एक प्रमुख चुनौती जनसामान्य में तकनीकी जानकारी और जागरूकता की कमी है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। अनेक लोग इसे जटिल और महंगा मानते हैं, जिससे इसका व्यापक स्तर पर क्रियान्वयन प्रभावित होता है। तकनीकी विशेषज्ञता की कमी, गलत डिज़ाइन और रखरखाव में लापरवाही के कारण कई प्रणालियां विफल हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त, वित्तीय बाधाएं भी हैं।

जमीन के बंटवारे को लेकर भाइयों में खूनी संघर्ष

भाई व भाभी को फावड़े व लाठियों से पीटा

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। महाराजपुर थाना क्षेत्र में जमीन के बंटवारे को लेकर भाइयों में खूनी संघर्ष हो गया। घटना में दबंगों ने भाई व भाभी को फावड़े और लाठियों से पीट दिया। पीड़ित ने स्थानीय चौकी, थाने व एसीपी कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया है। कानपुर में महाराजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत डोमनपुर का मजरा कपूर फॉर्म के रहने वाले एक किसान परिवार का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है।

पीड़ित राम प्रसाद पुत्र सदासुख ने बताया कि 12 मई की सुबह घर व जमीन के बंटवारे को लेकर भाई संतोष ,छोटू , सुखदेई व ज्योति और आंचल द्वारा मुझे व मेरी पत्नी नीलम को भद्दी-भद्दी गालियां देने लगे। इसका विरोध किया, तो सभी ने मिलकर लाठियों से पीटा है।

जाते वक्त जान से मारने की नीयत से फावड़ा उठाकर दौड़ा लिया गया। किसी तरह भाग कर मैंने अपनी जान बचाई है। पीड़ित राम प्रसाद ने बताया कि वह स्थानीय चौकी गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद वह थाने गया और वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।

दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई

इस पर 17 मई को एसीपी कार्यालय में जाकर न्याय की गुहार लगाई थी। यहां से मुकदमा पंजीकृत करने का आश्वासन मिला था। 11 दिन बीतने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। कई दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित ने बताया यदि कार्रवाई नहीं होती, तो वह उच्चाधिकारियों की चौखट पर न्याय की गुहार लगाएगा।

जवानों के अदम्य साहस एवं शौर्य को किया गया नमन

विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म महाविद्यालय नवाबगंज कानपुर में शिक्षणेत्तर कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित किया गया कार्यक्रम

स्वराज इंडिया संवाददाता

कानपुर। विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म महाविद्यालय नवाबगंज कानपुर में शिक्षणेत्तर कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम मे ऑपरेशन सिन्दूर की सफलता में भारतीय सेना के जवानों के अदम्य साहस एवं शौर्य को कोटि कोटि बधाई प्रेषित की गई। साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की गई।इस अवसर पर प्रबंध समिति के संयुक्त सचिव डॉ. कमल किशोर गुप्ता,प्राचार्य प्रो.बिपिन चंद्र कौशिक,उप प्राचार्या प्रो.नीरू टंडन, सम्पति अधिकारी अंशू सेंगर,विभाग प्रभारी प्रो. नन्दलाल,प्रो.आशीष सिंह संघ के अध्यक्ष विवेक मिश्र, महामंत्री नितिन मिश्र,संयुक्त मंत्री सी.एस.जे.एम.अनिल कुशवाहा,सुभाष तिवारी चंद्रशेखर,अमित शर्मा, दीपक अवस्थी,सुरेन्द्र कुमार,अभिनव सिंह आदि उपस्थित रहें। मंच का संचालन प्रो. मनोज भूषण पाण्डेय जी द्वारा किया गया।

श्री गौरी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर
(AN ISO 9001:2015 CERTIFIED HOSPITAL)
यू.पी.एस.आई.डी.सी. जैनपुर, कानपुर देहात
Mob: 9710106661, 73310106662, 7310106663
अल्ट्रासाउण्ड, सी.टी. स्कैन, डिजिटल एक्सरे की 24 घंटे सुविधा उपलब्ध
- आई0सी0यू0/सी0सी0यू0।
- वेंटीलेटर, ए0वी0जी0ए0, कारडियक मॉनीटर, मल्टीपैरा मॉनीटर की सुविधा।
- C-Arm युक्त वतानुकूलित ऑपरेशन थियेटर।
- ट्रामा स्पोर्ट हेड इन्जुरी का सफल इलाज।
- डिजिटल एक्स.रे, सी.टी. स्कैन, अल्ट्रासाउण्ड (U.S.G.) की सुविधा

आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज उपलब्ध है।
टी.पी.ए. कैशलेस की सुविधा उपलब्ध
उपलब्ध सुविधाएं:- ए0बीजी0ए0 मशीन
1. अत्यंत कम वजन के नवजात शिशु एवं समय से पहले जन्में शिशुओं की विशेष देखभाल। 2. नवजात एवं बाल्य गहन चिकित्सा इकाई ;च्ण्ब्ण्न्द्ध 3. चौबीस घंटे मेडिकल स्टोर, एक्सरे, पैथालॉजी, कैन्टीन की सुविधा। 4. नि:शुल्क एम्बुलेंस की सुविधा। 5. दूरबीन द्वारा पित्त एवं गुर्दे, यूरेटर की पथरी का ऑपरेशन, बच्चेदानी में गांठ का ऑपरेशन दूरबीन द्वारा किया जाता है। 6. गहन चिकित्सा इकाई, वेंटीलेटर सुविधा सहित। 7. सभी प्रकार के हड्डी रोग एवं ट्रामा सम्बंधित ऑपरेशन। 8. सिजेरियन ऑपरेशन/डिलेवरी/बच्चेदानी का ऑपरेशन अत्याधुनिक ऑपरेशन थियेटर। 9. कार्डियक मीनीटरिंग/इको कार्डियोग्राफी/सोनोग्राफी/टी.एम.टी.
डा. संजय त्रिपाठी
एम.बी.बी.एस., एमडी मेडिसिन
फेलोशिप क्रिटिकल केयर
विजय बाजपेई
मैनेजिंग डायरेक्टर

कलेक्ट्रेट में बिना छुट्टी सीट से नदारद बाबू, जनता परेशान

सहकर्मियों ने बताया कि यूनुस खान बाबूजी हर शुक्रवार बिना बताए नवाज अदा करने चले जाते हैं

स्वराज इंडिया संवाददाता

कानपुर। अपर जिलाधिकारी कार्यालय वित्त एवं राजस्व जनपद कानपुर देहात माती मुख्यालय में बाबू के पद पर कार्यरत यूनुस खान जो कि बगैर छुट्टी के ही ड्यूटी के दौरान नमाज अदा करने चले जाते हैं।

हुआ यूं कि एक स्टांप वेंडरशिप की फाइल जो की सारी औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद भी 15 दिन से यूनुस बाबू द्वारा एक लाख रुपया घूस मांगे जाने के कारण एवं आवेदक द्वारा घूस न दिए जाने की वजह से 15 दिन से फाइल अप्रूवल नहीं हुई है। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट आदेश है कि कोई भी फाइल किसी पटल पर 3 दिन से ज्यादा पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए , प्रदेश के मुखिया के आदेश के

बावजूद भी फाइल 15 दिन से अपर जिलाधिकारी कार्यालय में पेंडिंग थी जिसकी सत्यता पता करने के क्रम में हमारे संवाददाता द्वारा अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व के कार्यालय पहुंचा, जहां पर आज शुक्रवार का दिन था समय लगभग 1-50 पर यूनुस खान बाबू कार्यालय में उपलब्ध नहीं थे।

जानकारी करने पर सहकर्मियों ने बताया कि यूनुस खान बाबूजी नवाज अदा करने गए हैं जबकि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप कार्य दिवस में कार्यवधि के दौरान इस तरीके से नवाज अदा करने अपने ड्यूटी के घंटे में ,ड्यूटी को छोड़कर जाए, वही हमारे संवाददाता द्वारा इस मामले के बावत अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व जनपद कानपुर देहात दुष्यंत मौर्य से बातचीत की गई। उनके द्वारा बताया गया कि ऐसी कोई भी जानकारी मेरे पास नहीं है एवं मामले का स्पष्ट जवाब देने से बचते हुए दिखे,वीडियो वायरल हुआ है देखते हैं आगे जिम्मेदार लोग क्या कार्रवाई अमल में लाते हैं जबकि ऐसे मामलों में उत्तर प्रदेश सरकार यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा द ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है

शिवराजपुर में सड़क हादसा, 2 की मौत

» शिवराजपुर सखरेज मार्ग पर हुई दुर्घटना

» कार और बाइक में हुई जोरदार टक्कर जेल

स्वराज इंडिया संवाददाता

बिल्हौर (कानपुर)। शिवराजपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर हुए सड़क हादसे ने दो जिंदगियां समाप्त कर दी।जिससे दो परिवारों की खुशियाँ बिखर गई।

दुर्घटना शिवराजपुर के सखरेज मार्ग पर हुई। तेज रफ़्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी।टक्कर इतनी जोरदार थी,कि बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।कार सवार एक व्यक्ति घायल हुआ है।जानकारी के मुताबिक बीरामऊ गांव के महेंद्र और कुकुरी गांव के भूपेंद्र बाइक द्वारा बीरामऊ से शिवराजपुर की ओर जा रहे थे। तभी शिवराजपुर थाना क्षेत्र के सखरेज की तरफ जा रही तेज रफ्तार ईको कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।टक्कर इतनी जबरदस्त थी की कार खेत मे जा घुसी। और बाइक सड़क किनारे खाई मे जा गिरी।दुर्घटना मे तीन लोग घायल हुए।

स्थानीय लोगों की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से तीनो घायलों को सीएचसी पहुंचाया । जहां डॉक्टरो की टीम ने बाइक सवार महेंद्र 27वर्ष और भूपेंद्र 30वर्ष को मृत घोषित कर दिया।पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

बॉम्बे हॉस्पिटल
नियर आघू रोड, कानपुर-आगरा हाईवे, अकबरपुर, कानपुर देहात

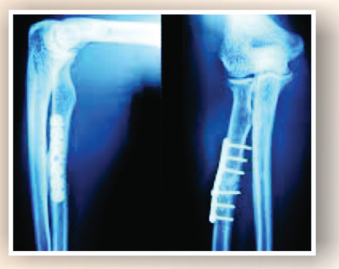

24 घंटे इमरजेंसी सुविधा
24 घंटे एम्बुलेंस व मेडिकल स्टोर की सुविधा
दूरबीन विधि द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन
हेल्पलाइन नं.: 8355017999, 8858997333

हड्डी के सभी ऑपरेशन, गुर्दे की पथरी
पित्ताशय की पथरी, फिशर, नासूर
अपेन्डिक्स, प्रोस्टेट, कैंसर की गांठ, भगंदर
हर्निया, हाइड्रोसील, छाती का कैंसर
पेट की चोट व अन्य समस्याएं
बच्चेदानी व अण्डाशय की गांठ
घुटने का प्रत्यारोपण, पाइल्स (बवासीर)

डॉ. सुरेश यादव
डायरेक्टर

साढ़े तीन साल से अधूरा पड़ा शौचालय

मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और डीएम के आदेशों के बावजूद नहीं खुला ताले में बंद सामुदायिक शौचालय, करोड़ों खर्च का हिसाब अधूरा, खुले में शौच को मजबूर ग्रामीण

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। भोगनीपुर चौराहे पर वर्षों से लंबित सामुदायिक शौचालय निर्माण का मामला सरकार की तमाम योजनाओं और निर्देशों की पोल खोल रहा है। वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और तत्कालीन जिलाधिकारी नेहा जैन ने महिलाओं की सुविधा को देखते हुए तत्काल शौचालय निर्माण के निर्देश दिए थे। प्रशासन ने आदेश के पालन में अधिकारियों को ज़िम्मेदारी भी सौंपी, लेकिन ढाई साल बीत जाने के बाद भी शौचालय या तो अधूरा है या ताले में बंद पड़ा है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि चौराहे पर महिलाओं और यात्रियों को खुले में शौच जाना पड़ता है, जिससे आए दिन शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। स्वच्छ भारत मिशन की असलियत इस अधूरे निर्माण से सामने आ गई है, और यह मामला अब केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार की बू देने लगा है।

-निर्माण में भारी गड़बड़झाला, जांच भी दबा दी गई

शौचालय निर्माण में नरेगा श्रमिकों से काम करवा कर पेमेंट बाहरी मजदूरों के नाम से उठाया गया। सूत्रों के मुताबिक, शौचालय की दीवारें पुरानी खुदाई की ईंटों से बनाई गई हैं, जबकि बजट में नई ईंटें दिखाकर लाखों रुपये खर्च दर्शाए गए। मामले की शिकायत पर जिला स्तरीय जांच भी हुई, जिसमें अनियमितताएं उजागर हुईं, लेकिन आज तक किसी पर कार्रवाई नहीं हुई।गांव की महिलाओं और सामाजिक संगठनों का कहना है कि शौचालय तैयार होने के बावजूद जनता के लिए नहीं खोला गया ताकि फर्जी बिल और पेमेंट का खेल चलता रहे। सवाल यह है कि जब शासन से लेकर जनप्रतिनिधि तक आदेश दे चुके हैं, तब भी ब्लॉक, ग्राम पंचायत और संबंधित अधिकारियों की चुप्पी क्यों? यह शौचालय अब जनहित की जरूरत नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार की नजीर बनता जा रहा है।

जल जीवन मिशन फेल: 3500 की आबादी पानी को तरस रही

» मलासा गांव की टंकी बनी सफेद हाथी, तीन दिन से बंद पड़ी जल आपूर्ति, अधिकारी बेपरवाह

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। मलासा गांव में जल जीवन मिशन के तहत लाखों रुपये खर्च कर बनाई गई पानी की टंकी तकनीकी खामियों के कारण गांववालों के किसी काम नहीं आ रही। पिछले तीन दिनों से अधिक समय से जल आपूर्ति पूरी तरह ठप है, जिससे 3500 की आबादी पेयजल संकट से जूझ रही है। पानी की लाइन में लीकेज और तकनीकी खराबी के चलते टंकी से जल वितरण बंद हो गया है। हालत यह है कि जिन हैंडपंपों को लोगों ने लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया, वे भी अब खराब हो चुके हैं।

खास खबर

सरकार की मंशा थी कि जल जीवन मिशन से हर घर तक शुद्ध पानी पहुंचे, लेकिन योजना का क्रियान्वयन इतना लचर है कि अब गांवों में पानी की तलाश में भटकाव शुरू हो गया है। विभागीय अधिकारी मौके पर निरीक्षण तक करने नहीं पहुंचे, जिससे लोगों में रोष गहराता जा रहा है।

जिम्मेदारों की अनदेखी, गांव में मचा हाहाकार

गांववालों का कहना है कि अगर अधिकारी समय रहते पानी की टंकी और पाइपलाइन की जांच करते तो यह संकट पैदा नहीं होता।

लेकिन आज भी विभाग तकनीकी खामियों को ठीक करने में गंभीरता नहीं दिखा रहा। नतीजतन, महिलाएं और बुजुर्ग पानी के लिए हैंडपंप और दूसरे गांवों पर निर्भर हो रहे हैं।

जब इस बारे में जल निगम के सहायक अभियंता संजय सिंह से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि मामले की जानकारी नहीं थी, जल्द ही जल आपूर्ति बहाल की जाएगी। सवाल यह है कि तीन दिन बाद भी जब अधिकारी अनजान हैं, तो जिम्मेदारी किसकी है? और गांव के लोगों की परेशानियों का हल कब निकलेगा?

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सपना देवी द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। **संपादक:** अनूप कुमार **RNI No.:** UPHIN/2023/86769 | **Email:** swarajindia2023@gmail.com | **Mob:** 7800009853, | **Website:** www.swarajindianews.com | (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे)

आंधी से कई गांव की बिजली उड़ी

» तूफान ने गिराया बिजली का पोल, गांवों में अंधेरा और पानी का संकट

» 35 से ज्यादा गांवों की सप्लाई ठप, हैंडपंपों पर लगी लंबी कतारें, जल जीवन मिशन भी फेल

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। तेज आंधी और बारिश ने जिलेभर में बिजली व्यवस्था की पोल खोल दी है। बुधवार रात आई तेज हवाओं के साथ तूफान ने मुतैहेरापुर सबस्टेशन से जुड़े 35 से अधिक गांवों को अंधेरे में डुबो दिया। पूरी रात ग्रामीण बिजली का इंतजार करते रहे लेकिन विभाग की तरफ से सिर्फ आ रही है, आ रही है जैसे आश्वासन ही मिलते रहे।

विद्युत आपूर्ति ठप होने से लोगों को पीने के पानी के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ी। जल जीवन मिशन की पाइपलाइनों से पानी नहीं आया, जिससे सुबह होते ही हैंडपंपों पर लंबी कतारें लग गईं।

कई जगह तो ग्रामीणों को दूर-दराज के खेतों और टैंकरों से पानी लाना पड़ा।

ग्रामीणों ने बताया कि 33 केवी लाइन सालों से जर्जर है,

जिससे हर आंधी-तूफान के बाद बिजली गायब हो जाती है। इससे न सिर्फ पेयजल संकट गहराता है बल्कि बच्चों की पढ़ाई और किसानों की सिंचाई भी प्रभावित होती है।

क्या बोले जिम्मेदार अधिकारी

इस पूरे मामले पर जेई अजय कुमार ने बताया कि आंधी से कई जगहों पर लाइन के इंसुलेटर टूटे और तार गिर गए हैं। काम जारी है, शाम तक सप्लाई बहाल हो जाएगी।लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कब तक ग्रामीण हर मौसम के बाद इस संकट से जूझते रहेंगे? क्या जर्जर लाइन की मरम्मत विभाग की प्राथमिकता नहीं है?

घाटमपुर के पास रजवाहा फटने से कई गांव जलमग्न, सिंचाई विभाग बना मूकदर्शक

उमरन झील भरने के नाम पर रोकी गई खांधी, न पानी आगे पहुंच रहा, न गांवों का बच रहा नुकसान

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। घाटमपुर क्षेत्र के बलवा हार गांव के पास रजवाहा की पटरी फटने से भारी जलभराव की स्थिति बन गई है। बीते तीन दिनों से लगातार बहते पानी ने पांच गांवों को जलमग्न कर दिया है और करीब 500 बीघा फसल बर्बाद हो चुकी है। ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग को कई बार सूचना दी, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। विभागीय लापरवाही के चलते मूंग की खड़ी फसल और चारे की बुवाई पानी में डूब चुकी है, जिससे किसानों में भारी आक्रोश है।

ग्रामीणों का कहना है कि अफसर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि गांववाले खुद पटरी बांध दें। वहीं, गंग नहर विभाग द्वारा छोड़ा गया पानी उमरन झील भरने के लिए खांधी के माध्यम से डायवर्ट किया जा रहा है, जिसके कारण आगे रजवाहा सूखा पड़ा है और अन्य तालाब पानी को तरस रहे हैं। सवाल यह उठ रहा है कि क्या उमरन झील भरने के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है?

क्या बोले जिम्मेदार

सिंचाई विभाग के एसडीओ ओमप्रकाश दिनकर से संपर्क नहीं हो सका। वहीं विभाग के जेई ने बताया कि उमरन की करीब 100 एकड़ झील को भरा जा रहा है, इसलिए खांधी को बंद नहीं किया जा सकता। झील भरते ही पटरी की मरम्मत कर दी जाएगी।

ग्रामीणों की पीड़ा और अधिकारियों की उदासीनता ने एक बार फिर यह उजागर कर दिया है कि सरकारी तंत्र आमजन की तकलीफों से कितना दूर है।

अयोध्या के लाल लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी शहीद

» शौर्य की मिसाल बन वीरगति को किया वरण

» वीर सपूत ने साथी को बचाते हुए दी प्राणों की आहुति

स्वराज इंडिया संवाददाता

अयोध्या। देशभक्ति, वीरता और कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल पेश करते हुए अयोध्या जनपद के मंझवा गद्दोपुर गांव के युवा लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी ने गुरुवार को सिक्किम में अपने साथी सैनिक की जान बचाते हुए वीरगति को प्राप्त कर लिया। उनकी पहली तैनाती ही देश के लिए आखिरी साबित हुई।

24 जनवरी 2002 को जन्मे शशांक ने 14 दिसंबर 2024 को भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त किया था। वर्तमान में वे सिक्किम स्काउट्स बटालियन में तैनात थे। गुरुवार सुबह 11:10 बजे तब हुई जब सिक्किम के टीओबी चू जंक्शन के लिए रूट ओपनिंग का कार्य चल रहा था। इस दौरान एवी स्टीफन सुब्बा लॉग ब्रिज पार करते हुए तेज बहाव में गिर पड़े। साथी को संकट में देखकर शशांक ने बिना एक पल गंवाए नदी में छलांग लगा दी और स्टीफन को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन तेज धारा उन्हें अपने साथ बहा ले गई। तमाम प्रयासों के बावजूद उनका शव करीब 800 मीटर दूर बरामद हुआ।

शशांक के परिवार में उनके पिता जंग बहादुर तिवारी, माता नीता तिवारी और एक विवाहित बहन हैं। बृहस्पतिवार की सुबह ही शशांक ने अपनी मां से फोन पर बातचीत की थी, परंतु दोपहर तक खबर मौत की बनकर आई। इस खबर के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। मां की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे, पिता गहरे सदमे में हैं।शुक्रवार को शशांक का पार्थिव शरीर सैन्य सम्मान के साथ अयोध्या पहुंचेगा। शहीद स्मारक सेवा समिति के संरक्षक ओम प्रकाश नाहर ने इसकी जानकारी दी। शशांक तिवारी की शहादत न सिर्फ उनके परिवार के लिए, बल्कि पूरे जिले के लिए गर्व और गम का मिश्रण बन गई है। उन्होंने अपने जीवन की आहुति देकर यह दिखा दिया कि भारतीय सेना के जवान अपने साथियों और देश के लिए प्राण देने में भी पीछे नहीं रहते।

प्रभु श्रीराम ने जिस नदी को सिंधु समान बताया नगर निगम ने बताया नाला

» जहाँ बहती थी आस्था की धारा, वहाँ अब बह रहा है सिस्टम का सड़ा हुआ पानी

स्वराज इंडिया संवाददाता

अयोध्या। अयोध्या की जिस पवित्र भूमि को त्रेता युग से ही धर्म, मर्यादा और आस्था का प्रतीक माना जाता है, वहीं आज एक पौराणिक नदी का अस्तित्व खतरे में है – नाम है तिलोदकी। वाल्मीकि रामायण और स्कंद पुराण जैसे धर्मग्रंथों में तिलोदकी का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि यह नदी स्वयं भगवान श्रीराम के आदेश पर उत्पन्न हुई थी और इसे सिंधु नदी की समानता दी गई थी। इसका जल काले तिल के रंग जैसा था, इसलिए इसे तिलोदकी कहा गया। संतों का मानना है कि यह नदी तर्पण, श्राद्ध और पितृकार्य के लिए अत्यंत पुण्यदायी है।

स्थानीय लोगों के अनुसार–गद्दोपुर क्षेत्र से गुजरने वाली यह नदी कभी निर्मल जलधारा के रूप में बहती थी। ग्रामीण बताते हैं कि बचपन में लोग इस नदी से जल भरते थे, पिंडदान और स्नान करते थे। पास के मंदिरों में आज भी यह नदी विशेष पूजन में प्रयुक्त होती है।लेकिन आज की हकीकत क्या है?

नगर निगम की नज़रों में 'नाला–अयोध्या नगर निगम की आधिकारिक फाइलों और नक्शों में यह नदी अब एक ड्रेनेज चैनल यानि 'नाला' के रूप में दर्ज है। सरकारी रिकॉर्ड्स में इसके लिए किसी प्रकार की संरक्षण योजना तक नहीं बनाई गई।बदले में यहाँ अब शहर के सीवर, प्लास्टिक और घरेलू कूड़े का अंबार बहता है।

सिस्टम की बेरुख़ी या जानबूझकर किया जा रहा अपमान?

एक ओर जहां प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक आस्था की राजधानी

(स्वराज इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट)

अयोध्या के कायाकल्प की बात करते हैं, वहीं नगर निगम की नजरों में यह पौराणिक नदी मात्र एक गंदा नाला बन कर रह गई है। यह केवल पर्यावरणीय चिंता नहीं है, यह धार्मिक अस्मिता का खुला अपमान है।

स्थानीय विरोध और माँगें–ग्रामीणों और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे फिर से पवित्र नदी के रूप में पुनर्जीवित करने की माँग उठाई है। सरयू तट पर लाखों खर्च हो रहे हैं, लेकिन तिलोदकी को पूछने वाला कोई नहीं। जब भगवान राम ने इसे मान्यता दी, तो प्रशासन किस अधिकार से उसे नकार सकता है? बल्कि अयोध्या की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान है। यदि इसे 'नाला' कहकर भुला दिया गया, तो आने वाली पीढ़ियाँ न केवल एक पौराणिक नदी से वंचित होंगी, बल्कि उनकी आस्था की नींव भी दरक जाएगी।

अब सवाल अयोध्या से है — क्या तिलोदकी की पुकार सुनाई दे रही है? या यह नदी भी आस्था की राजनीति में गुमनाम हो जाएगी?

गंगा' को नाला कहने पर भड़के अभिषेक सावंत

इनका कहना है कि नाले का दर्जा रद्द हो तिलोदकी को दोबारा नदी माना जाए।राज्य विरासत में शामिल किया जाए धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर संरक्षण और पुनर्जीवन परियोजना बने।भाषा सुधारी जाए नगर निगम सिर्फ 'गंगा' या 'नदी' शब्द का उपयोग करे। रामायण काल में ऋषि रमणक की तपस्या से प्रकट हुई थी नदी। 1902 की तीर्थ विवेचनी सभा के शिला लेख में भी उल्लेख मिलता है। हंस बेकर, लाला सीताराम, राजकुमार दास और डॉ. देशराज उपाध्याय की पुस्तकों में वर्णन। पर्यटन विभाग की पत्रिका साक्षी में शामिल हर साल भाद्रपद अमावस्या को होता है कुशोदपाटिनी स्नान, हजारों श्रद्धालु जुटते हैं आस्था की डुबकी लगाने

स्वराज इंडिया कहता है

ये नाला नहीं, गंगा है! आस्था की धारा को फिर से बहाना होगा पहचान के साथ, सम्मान के साथ।

धूल रहित थ्रेशर का मॉडल बनाकर पूजा ने रोशन किया नाम

» राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया मॉडल

» पूजा की प्रतिभा का सफर दिसंबर 2020 में शुरू हुआ, जब उनका मॉडल जिला और मंडल स्तर पर चुना गया

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बाराबंकी । सिरौलीगौसपुर की छात्रा पूजा ने एक अनूठी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने धूल रहित थ्रेशर का मॉडल बनाया है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। पूजा के परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। उनके पिता मजदूरी करते हैं। और मां उसी सरकारी स्कूल में रसोईया हैं, जहां पूजा पढ़ती थी। परिवार घासफूस पन्नी से बनी झोपड़ी में रहता है। पूजा की प्रतिभा का सफर दिसंबर 2020 में शुरू हुआ, जब उनका मॉडल जिला और मंडल स्तर पर चुना गया। लखनऊ की राज्यस्तरीय प्रदर्शनी में उनका मॉडल राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित हुआ।

दिल्ली में आयोजित प्रदर्शनी में भी उनके मॉडल को सराहा गया। वर्ष 2024 में भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय विज्ञान मेले में पूजा का मॉडल चयनित हुआ। अब 14 जून को वह जापान जाएंगी। वहां वह अन्य भारतीय छात्रों के साथ टोक्यो की विश्वविद्यालयों और विज्ञान प्रयोगशालाओं का दौरा करेंगी।

वर्तमान में पूजा जगदीशचंद्र फतेहराय इंटर कॉलेज में कक्षा 9 की छात्रा हैं। उनके गाइड टीचर राजीव श्रीवास्तव के अनुसार, यह उपलब्धि न केवल पूजा के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है।

पूजा ने पूर्व माध्यमिक विद्यालय अगेहरा में कक्षा 8 की छात्रा थी तब यह मॉडल बनाया था। पूजा जिस विद्यालय में पढ़ती थी उसी विद्यालय में उनकी मां सुनीला रसोईया के पद पर कार्य कर रही है।छात्रा पूजा ने बताया कि स्कूल में पढ़ाई के दौरान बगल में थ्रेशर से हो रही गेहूं की मढ़ाई से धूल आ रही थी। इससे बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मैने अपने विज्ञान टीचर को आइडिया दिया कि थ्रेशर से धूल ही ना निकले तो बेहतर होगा। इसी के बाद मैने धूलरहित थ्रेशर का मॉडल टिन और पंखे से बनाया। जिसमें पंखा धूल बाहर उड़ने के बजाय एक थैले में जमा कर लेता है। इसके लिए उन्होंने करीब तीन हजार खर्च किए उन्होंने अध्यापक के सहयोग से यह कार्य पूरा किया।

5 भाई बहन है पूजा

पूजा पांच भाई बहन है पूजा तीन बहनों में दूसरे नंबर पर है तथा माता सुनीला रसोईया हैं पिता पुत्तीलाल मजदूरी करते हैं !

रामसनेहीघाट के लेखपाल का घूस लेते वीडियो वायरल

» तीन लोगों ने लेखपाल के खिलाफ की लिखित में शिकायत

स्वराज इंडिया संवाददाता

बाराबंकी । रामसनेहीघाट तहसील क्षेत्र के सड़वा भेलू के तीन लोगों ने क्षेत्रीय लेखपाल पर आय,नाम संशोधन व भूमि को दाखिल खारिज के नाम पर पैसे मांगने का आरोप लगाते हुए शिकायती पत्र उपजिलाधिकारी को दिया है।आरोप है कि लेखपाल द्वारा आय प्रमाण पत्र के आवेदन पर रिपोर्ट लगाने के लिए पैसे लेते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है।तहसील क्षेत्र के सड़वा भेलू गांव में तैनात लेखपाल पर गांव निवासियों ने काम के लिए पैसे मांगने का गंभीर आरोप लगाया है।लोगो के अनुसार तहसील संबंधी किसी भी कार्य के लिए लेखपाल द्वारा पैसा मांगा जाता है।पैसे न देने पर कार्य नहीं होता।और जो होता है उसमें भी कमियां निकाल दी जाती है।सड़वा भेलू निवासी रमेश अपने पुत्र मुरारीलाल के इलाज के लिए सहायता और अपने बुढ़ापे के लिए पेंशन बनवाने के लिए आय प्रमाण पत्र का बनवाने आवेदन किया था। लेखपाल दीपचंद्र श्रीवास्तव ने आवेदन पर रिपोर्ट लगवाने के लिए एक हजार रुपए की मांग की।बुजुर्ग रमेश ने बहुत मिन्नतें की तो उन्होंने दो सौ रूपए वापस कर पांच सौ की दो नोट रख लिए पास खड़े व्यक्ति ने लेन देन का वीडियो बना लिया। और उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया हालांकि हमारा समाचार पत्र इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।रमेश ने आय प्रमाण पत्र के अतिरिक्त खतौनी में अंश दुरुस्ती के लिए आवेदन किया था।लेखपाल ने बैनामा दुरुस्ती के लिए पचास हजार की मांग की।रमेश ने बताया कि उनके पुत्र मुरारी के दोनो फेफड़ों में मवाद भर जाती है।जिसका इलाज कई वर्षों से चल रहा है। इसको लेकर विगत 2015 में अपने चार बीघे के हिस्से में एक बीघे खेत की बिक्री की थी किंतु खेतौनी में आधा हिस्सा की बिक्री चढ़ गई थी।जिसको दुरुस्त करवाना था।उसके लिए लेखपाल ने पचास हजार की मांग की थी।बहुत मिन्नत करने पर पैतालीस हजार की बात हुई ।किंतु पैसा न देने पर खेतौनी में हिस्सा दुरुस्त

नहीं हुआ।रमेश ने उपजिलाधिकारी को दोनों मामलों की जानकारी देते हुए शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है।सड़वा भेलू निवासी रमेश पुत्र रामधीरज ने उपजिलाधिकारी को क्षेत्रीय लेखपाल के खिलाफ प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उन्होंने फूलमता से एक जमीन बैनामा करवाया था।लेखपाल घर गए और दाखिल खारिज के लिए पांच हजार रुपए मांगे।मना करने पर उन्होंने दाखिल खारिज नहीं किया।रमेश ने बताया कि लेखपाल गांव में कहते थे कि बगैर पैसे के बस्ता नहीं खुलता।पैसा न देने की बात पर उन्होंने धमकी दी कि कागज पर ऐसा लिख दूंगा कि भविष्य में दाखिल खारिज नहीं होगा।उसी गांव के हनुमान पुत्र प्रभु ने उपजिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि अपनी भूमि की पैमाईश के लिए प्रार्थना दिया।लेखपाल द्वारा दस हजार की मांग की।पैसे नहीं दिया अभी तक पैमाईश नहीं हुई।वीडियो वायरल होने पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया।जिसके बाद तहसील प्रशासन ने निलंबित कर दिया। उपजिलाधिकारी अनुराग सिंह जांच कराई जा रही है।

पाकिस्तान के खात्मे का समय आ गया 75 साल बहुत जी लिया: सीएम योगी

वहां का आतंकवाद ही उसे ले डूबेगा, लकीर का फकीर बनने से फायदा नहीं

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे। उन्होंने यहां हनुमानगढ़ी में बने श्री हनुमत कथा मंडप लोकार्पण किया। योगी ने कहा कि 500 साल के अंतराल के बाद रामनगरी अयोध्या का वैभव वापस लौटा है। एक समय सुविधाओं के अकाल से जूझ रही अयोध्या का कायाकल्प हो गया है। उन्होंने कहा कि मंदिर यहीं बनाने का सौगंध खाया था और संकल्प को सिद्ध भी किया। योगी ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को लेकर जमकर निशाना साधा।

सीएम योगी ने कहा, पाकिस्तान अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। वहां का आतंकवाद ही उसे ले डूबेगा। पाकिस्तान 75 साल बहुत जी लिया और अब खात्मे का समय आ गया है। वह अपने ही कर्मों का फल भुगत रहा है। यह नया भारत है, जो किसी को छेड़ता नहीं है। लेकिन कोई छेड़े तो छोड़ता भी नहीं है। हमने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया। एयर डिफेंस सिस्टम ने हर हमला फेल किया।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश और धर्म के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं है। हमारा अस्तित्व सनातन की वजह से है। पाकिस्तान का अपना कुछ नहीं है, सब कृत्रिम है। पहलगाम में लोगों का धर्म पूछकर मारा गया। लेकिन पाकिस्तान को हमारे 24 लोगों की जान की कीमत 124 आतंकियों की जिंदगी से चुकानी पड़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने एक दिवसीय दौरे में वह कई कार्यक्रमों में भागीदारी करेंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत में नए नेतृत्व के उदय के साथ ही अब दुनिया नये भारत की बात करने लगी है। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। ये सिर्फएक दशक पहले की ही बात है। उत्तर प्रदेश और भारत के लोग दुनिया में कहीं जाते थे तो खुद को भारतीय कहने पर थोड़ा संकोच करते थे पर अब गर्व से खुद को भारतीय कहते हैं क्योंकि दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। यूपी के लोग कहीं बाहर जाने पर खुद को उत्तर प्रदेश का बताने पर संकोच करते थे पर अब वो गर्व से खुद को उत्तर प्रदेश का नागरिक बताते हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक बार यूरोप गया था और वहां पर घूमने निकला और एक टैक्सी पर बैठा। मुझे टैक्सी वाला भारत का निवासी लगा। मैंने पूछा कि कहां के हो तो उसने कहा पंजाब का। मैंने पूछा पंजाब में कहां से तो चुप हो गया... फिर बताया कि पाकिस्तान से हैं। उसने मुझे बताया कि भारत का बताने पर हम यहां पर सेफमहसूस करते हैं।

अयोध्या पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी में बने श्री हनुमत कथा मंडप लोकार्पण कर श्री रामलला के दर्शन किए।

युवाओं को वितरित किया 47 करोड़ का ऋण

मुख्यमंत्री योगी रामकथा पार्क पहुंचे और मुख्यमंत्री उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत आयोजित स्टार्टअप प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस मौके पर उन्होंने युवाओं को 47 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया और उनसे उद्यम अपनाने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर हैं। सुबह करीब सवा 10 बजे उनका हेलीकॉप्टर अयोध्या के रामकथा पार्क में लैंड हुआ। यहां से वह रामलला का दर्शन करने के लिए रवाना हो गए। उन्होंने पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन किए और फिर रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। आज करीब साढ़े चार घंटे अयोध्या में रहेंगे।

मुख्यमंत्री 0ने महाराजा पैलेस राज सदन में दो दिनों तक चलने वाले साहित्य उत्सव टाइमलेस अयोध्या का शुभारंभ किया। यहां पर उनके साथ प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, प्रख्यात लोक गायिका मालिनी अवस्थी, संगीत अध्येता और आयोजक यतींद्र मिश्र भी मौजूद रहे।

राजकीय महाविद्यालयों में 1207 प्राचार्य व शिक्षकों की होगी भर्ती

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। यूपी के 71 महाविद्यालयों को नए सत्र 2025-26 से राजकीय महाविद्यालय के रूप में चलाने का निर्णय लिया है। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने 1207 प्राचार्य व शिक्षकों के पद सृजित किए हैं। इन पदों पर भर्ती की जाएगी। साथ ही पदोन्नति से 142 तृतीय श्रेणी कर्मचारी (प्रधान व वरिष्ठ सहायक) और 710 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आउटसोर्सिंग से रखने का फैसला किया है।

विभाग के अनुसार इन महाविद्यालयों में एक-एक प्राचार्य, कला संकाय में आठ-आठ असिस्टेंट प्रोफेसर, विज्ञान संकाय में पांच-पांच असिस्टेंट प्रोफेसर व एक-एक प्रवक्ता (लाइब्रेरी) के पदों पर भर्ती होगी। इस तरह प्राचार्य के 71, असिस्टेंट प्रोफेसर के 1136 व प्रवक्ता पुस्तकालय के 71 समेत कुल 1207 पदों पर लोक सेवा आयोग से भर्ती होगी। प्रति महाविद्यालय प्रधान व वरिष्ठ सहायक के एक-एक समेत कुल 142 पद वरिष्ठ सहायक व कनिष्ठ सहायक से पदोन्नति से भरे जाएंगे।

उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव गिरिजेश त्यागी की ओर से उच्च शिक्षा निदेशक को भेजे निर्देश में कहा गया है कि इन महाविद्यालयों के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रति महाविद्यालय 10, कुल 710 को आउटसोर्सिंग से रखा जाएगा।

उच्च शिक्षा निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित पद मानक व न्यूनतम कार्य आवश्यकता के अनुरूप हैं। पद सृजन के साथ ही जल्द इनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इससे प्रदेश में राजकीय महाविद्यालयों की संख्या 171 से बढ़कर 242 हो जाएगी।

शोक की लहर

राज्य सूचना आयुक्त गिरजेश चौधरी का दिल का दौरा पड़ने से निधन

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त गिरजेश चौधरी का शुक्रवार को बस्ती में एक सरकारी कायक्रम के दौरान दिल का दौरा पड़ने से आकस्मिक निधन हो गया। 62 वर्षीय चौधरी गुरुवार तक पूरी सक्रियता से कार्य कर रहे थे। उनके निधन से प्रशासनिक क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है।

उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक तंत्र को शुक्रवार को उस समय गहरा आघात पहुंचा, जब राज्य सूचना आयुक्त गिरजेश चौधरी का अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 62 वर्षीय चौधरी शुक्रवार को बस्ती जिले में एक सरकारी कार्यक्रम में भाग लेने गए थे। वहां अचानक उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई। मौके पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों ने तुरंत प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई और उन्हें गंभीर हालत में लखनऊ के लारी कार्डियोलॉजी संस्थान लाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

योगी सरकार ने मानदेय को लेकर किया एलान

खुशखबरी : आउटसोर्स कर्मियों मिलेंगे न्यूनतम 16 हजार से 18 हजार रुपये

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। योगी सरकार ने विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 808736.06 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। एक बड़ा निर्णय लेते हुए सरकार ने आउटसोर्स कर्मियों का पारिश्रमिक न्यूनतम 16 हजार से 18 हजार रुपये तक करने का एलान किया है। अभी तक उन्हें आठ-दस हजार रुपये ही मिलते थे। इसकी प्रक्रिया को सुनियोजित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन भी किया जाएगा।

अपने नौवें बजट में योगी सरकार ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास के जरिये एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का आकार पाने के लक्ष्य की ओर मजबूती से कदम बढ़ाने का हौसला दिखाया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में व पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह की ओर से विधान परिषद में प्रस्तुत किए गए बजट में सरकार ने भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए वादे को निभाते हुए उच्च शिक्षा में मेधावी युवा छात्राओं को स्कूटी देने की घोषणा की है। कनेक्टिविटी बढ़ाकर आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए खजाना खोला है। आगामी पंचायत चुनाव पर नजरें गड़ाए हुई सरकार ने खेती-किसानी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी बजट में भरपूर आवंटन किया गया है।

वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना की घोषणा कर उत्तर प्रदेश को प्रौद्योगिकी के वैश्विक मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने का दम भी दिखाया है। विकास कार्यों को नई ऊंचाइयां देने के लिए बजट में 2.26 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत परिव्यय के मद में आवंटित किए गए हैं। बजट में 28,478.34 करोड़ रुपये की नई योजनाएं शामिल है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट का आकार 2024-24 की तुलना में 9.8 प्रतिशत अधिक है। मुख्यमंत्री ने जिला मुख्यालय वाले नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित किए जाने की बात कही। कानपुर, मेरठ, मथुरा के इन्फ्रास्ट्रक्चर को प्रयागराज की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने विधान भवन के तिलक हॉल में प्रेस कान्फ्रेंस कर सरकार की मंशा को सामने रखते हुए इसे विस्तार दिया।

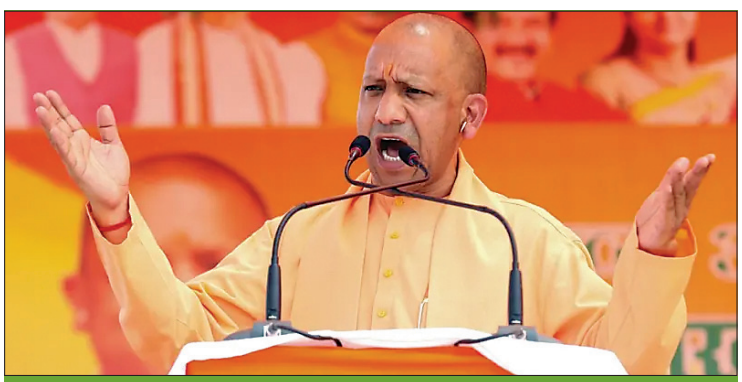

आउटसोर्स कर्मियों के लिए बड़ा निर्णय

एक बड़ा निर्णय लेते हुए सरकार ने आउटसोर्स कर्मियों का पारिश्रमिक न्यूनतम 16 हजार से 18 हजार रुपये तक करने का एलान किया है। अभी तक उन्हें आठ-दस हजार रुपये ही मिलते थे। इसकी प्रक्रिया को सुनियोजित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 51 हजार रुपये की धनराशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये और विधवा पुनर्विवाह व उनकी पुत्रियों के विवाह के लिए अनुमन्य सहायता राशि को भी एक लाख रुपये कर दिया गया है।

चार नये एक्सप्रेसवे के लिए 1050 करोड़ का प्रावधान

बजट में चार नये एक्सप्रेसवे के लिए 1050 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके अलावा प्रयागराज में दो नये पुलों के निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। सभी मंडल मुख्यालयों पर विकास प्राधिकरणों, नगर निकायों द्वारा कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। ग्राम पंचायतों में वैवाहिक उत्सव एवं अन्य सामाजिक आयोजनों के लिए उत्सव भवन निमाज़्ण की योजना पर कार्य किया जाएगा। इसके अलावा 250 करोड़ रुपये जीरो पावर्टी अभियान के लिए प्रस्तावित है।